



यू० पी० बैंक इम्प्लाइज यूनियन

पंजीकरण संख्या-538

ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध

केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा-282002

पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा-282 001, मो: 09837472750

फोन/फैक्स: (नि०) 0562-4044383, E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com



परिपत्र संख्या : 2019-22 / 119 / 2020

दिनांक : 20.07.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

बैंक राष्ट्रीयकरण की 51वीं वर्षगांठ – 19 जुलाई 1969–2020

बैंक राष्ट्रीयकरण की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर एआईबीईए के महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् द्वारा एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की गई थी तथा इसके साथ बैंकों के जानबूझकर चूककर्ताओं की सूची भी जारी की गई थी। हम इस विज्ञप्ति का अनूदित सार अपनी सभी इकाईओं एवं सदस्यों क सूचनार्थ नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

साथी सी.एच. वेंकटचलम्, महामंत्री, ऑल इंडिया बैंक इम्प्लाइज एसोसिएशन
द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्ति

18.7.2020

बैंक राष्ट्रीयकरण की 51वीं वर्षगांठ – 19 जुलाई 1969 – 2020

आत्म निर्भर हासिल करने के लिए हमारे बैंकों को सुदृढ़ करें

ऑल इंडिया बैंक इम्प्लाइज एसोसिएशन से, हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा इसकी 51वीं वर्षगांठ का अभिवादन करते हैं। हमारे देश में, इन राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वैविध्यपूर्ण आर्थिक विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका निभाई है। हमें गर्व है कि एआईबीईए ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए अभियान चलाने और संघर्ष करने में एक बड़ी भूमिका निभाई।

हम संघर्ष का नेतृत्व करने और 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हासिल करने के लिए अपने नेताओं साथी प्रभात कार (एआईबीईए के पूर्व महामंत्री) और साथी एच एल परवाना (एआईबीईए के पूर्व मंत्री) द्वारा निभाई गई अग्रणी भूमिका का स्मरण करते हैं।

- आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हरेक नुक्कड़ और जगह पर अपनी शाखाओं की संख्या में बढ़ते हुए बड़े पैमाने पर विकसित हुए हैं।
- आज सभी वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशि रु. 138 लाख करोड़ से अधिक है। इस प्रकार, आम आदमी की बचत बैंकों में सुरक्षित है।
- आज, आम आदमी बैंक शाखा में प्रवेश कर सकता है और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकता है।
- आज बैंकिंग ऋण सभी महत्वपूर्ण और बुनियादी क्षेत्रों – कृषि, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों, स्वास्थ्य और शिक्षा, ढांचागत विकास, निर्यात आदि के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

- आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में भारी मात्रा में निवेश कर रहे हैं जिससे विकास में तेजी आ रही है।
- आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रत्यक्ष रोजगार और अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों में, रोजगार सृजन में मदद करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वृद्धि और विकास के इंजन बन गए हैं। बैंक राष्ट्र निर्माण संस्थान हैं और हमें इन बैंकों को सुदृढ़ करना चाहिए।

जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले पांच दशकों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन्हें देश की आत्मनिर्भरता और आत्म निर्भर भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुदृढ़ किए जाने तथा और आगे ले जाने की आवश्यकता है।

हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कमजोर करके या हमारे बैंकों का निजीकरण करके आत्म निर्भर या आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की जा सकती। हमें अपने देश में निजी बैंकों का बहुत कट अनुभव है।

हमारे बैंकों द्वारा सामना की जाने वाली एकमात्र प्रमुख समस्या निजी कंपनियों और कॉर्पोरेटों द्वारा उभरते हुए और खतरनाक ढंग से बढ़ते हुए खराब ऋणों की है। अगर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाती है और पैसा वसूल किया जाता है, तो हमारे बैंक राष्ट्रीय विकास में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

चूककर्ताओं को रियायत देने और बचतों पर कम ब्याज दर के साथ बैंकिंग करने वाली जनता पर बोझ डालने और सेवा शुल्कों में वृद्धि के मौजूदा चलन को रोका जाना चाहिए।

बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाते हुए, हमारी निम्नलिखित मांगें हैं और हम इन पर अपने अभियान को जारी रखेंगे।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ किया जाये
- सभी बैंकों को पर्याप्त पूंजी प्रदान की जाये
- निजीकरण के प्रयासों को बंद किया जाये
- कॉर्पोरेट खराब ऋणों की वसूली के लिए कड़े उपाये किए जायें
- बैंक ऋण की जानबूझकर चूक को आपराधिक अपराध बनाया जाये
- सभी ऋण चूककर्ताओं के नामों को प्रकाशित किया जाये
- बैंक चूककर्ताओं को सार्वजनिक पद ग्रहण करने और चुनाव लड़ने से रोका जाये
- वसूली कानूनों को सुदृढ़ करें – आईबीसी की समीक्षा करें
- जमाराशियों पर ब्याज दर बढ़ाई जाये
- बैंकिंग सेवा के उपयोग के लिए आम लोगों पर सेवा शुल्कों को कम किया जाये
- ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए शाखाओं में पर्याप्त कर्मचारी प्रदान किये जायें
- सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजक बैंकों के साथ विलय किया जाये

एआईबीईए जल्द ही इन मांगों पर देशव्यापी अभियान शुरू करेगा।

शुरूआत करते हुए, हम आज उन 2426 कर्जदारों की सूची जारी कर रहे हैं जो जानबूझकर चूककर्ता हैं और सब मिलाकर बैंकों के रू. 147,350 करोड़ के देनदार हैं।